

बिनोद कुमार रॉय, सी.जे., एन.के. सूद और सूर्यकांत, न्यायमूर्ति के समक्ष

जसवंत सिंह बाम्बा, -याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2003 की संख्या 19040

1 नवंबर, 2004

आयकर अधिनियम, 1961- धारा. 29(2), 119(2)(बी), 237 और 239-परिसीमा अधिनियम, 1963- धारा.5-सीमा अवधि के बाद कर की अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा-केंद्रीय बोर्ड ने देरी की माफी के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया इसे याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है - धारा 237 किसी व्यक्ति को कर की अतिरिक्त राशि वापस करने का अधिकार देती है - धारा 239 रिफंड के लिए आवेदन करने का तरीका और ऐसे रिफंड का दावा करने के लिए सीमा की अवधि प्रदान करती है - धारा 239 किसी दावे पर विचार करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है सीमा की निर्धारित अवधि के बाद किए गए रिफंड के लिए - क्या बोर्ड के पास रिफंड के विलंबित दावे को स्वीकार करने की शक्ति है, हां- धारा.119(2)(बी) वास्तविक से बचने के लिए सीमा की अवधि से छूट देने की शक्ति से संबंधित है किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में कठिनाई-धारा 239 और 119(2) में विशेष रूप से रिफंड के दावों के लिए 1963 अधिनियम की धारा 5 का आवेदन शामिल है- विलंबित दावे पर विचार करने के लिए धारा 119(2) के तहत बोर्ड की शक्ति केवल 1963 अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को शामिल करते हुए, बोर्ड को धारा 229 के तहत प्रदान की गई अवधि की समाप्ति के बाद भी धन वापसी के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम माना गया है।

(निरंजन दास बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (2004) 266 आईटीआर 489, खारिज)

माना गया कि 1961 अधिनियम की धारा 29(2) के प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सीमा अधिनियम की धारा 5 विशेष या स्थानीय कानूनों के मामलों में उस हद तक लागू होगी, जिस हद तक उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। दूसरे शब्दों में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का सहारा केवल तभी नहीं लिया जा सकता जब इसे किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया हो। अधिनियम की धारा 239 ने परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के

अनुप्रयोग को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा है। वास्तव में, 1961 अधिनियम की धारा 239 और 119(2) को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का अनुप्रयोग रिफंड के दावों को 1961 के अधिनियम में विशेष रूप से शामिल किया गया है। इस प्रकार, 1961 अधिनियम की धारा 119(2) के तहत विलंबित दावे पर विचार करने के लिए बोर्ड को दी गई शक्ति सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों को शामिल करने के अलावा और कुछ नहीं है।

(पैरा 13.1, 13.2 एवं 13.3)

इसके अलावा, यह माना गया कि 1961 अधिनियम की धारा 119 (2) के तहत बोर्ड को प्रदत्त शक्ति के आधार पर, यह वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए अधिनियम की धारा 239 के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में धन वापसी के लिए आवेदन स्वीकार करने में पूरी तरह से सक्षम है।

(पैरा 14)

पी.सी. जैन, याचिकाकर्ता के वकील।

राजेश बिंदल, अधिवक्ता प्रतिवादियों की ओर से ।

### निर्णय

एन.के. सूद, न्यायमूर्ति.

(1) इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 237 के तहत आकलन वर्ष 1995-96 के लिए रिफंड दावा दायर किया था। चूंकि दावा अधिनियम की धारा 239 में निर्धारित सीमा अवधि के बाद किया गया था, इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत देरी की माफी के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") ने बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया है।, - आदेश दिनांक 25 मई, 2003 (अनुलग्नक पी-1) द्वारा याचिकाकर्ता ने इस आदेश पर आपत्ति जताई है।

(2) जब मामला एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिसमें हम में से एक

सदस्य थे, निरंजन दास बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड<sup>(1)</sup> में इस न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच का निर्णय, इस तर्क पर भरोसा किया गया कि अधिनियम की धारा 239 के अनिवार्य प्रावधान अधिनियम की धारा 119 के तहत निर्देशों के माध्यम से बोर्ड द्वारा छूट के लिए उत्तरदायी नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि निर्धारिती के साथ-साथ राजस्व के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 119(2)(बी) विशेष रूप से बोर्ड को ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जिन्हें निरंजन दास (सुप्रा) में विशेष रूप से नहीं देखा गया था। राजस्व के लिए विद्वान परामर्श ने यह भी बताया कि राजस्व ने भी निरंजन दास (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं किया था और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

(3) डिवीजन बेंच ने निरंजन दास (सुप्रा) में व्यक्त दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में अपने संदेह पर भी विचार किया और कानून के निम्नलिखित प्रश्न को पूर्ण बेंच द्वारा विचार के लिए भेजा: -

क्या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 239 में निर्धारित शर्तें अधिनियम की धारा 119 के तहत निर्देशों के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हाथों छूट के योग्य हैं?

(4) श्री पी.सी. निर्धारिती के विद्वान वकील जैन ने निम्नानुसार तर्क दिया:-

भारत के संविधान का अनुच्छेद 245 विधानमंडल को प्रशासनिक एजेंसियों को विभिन्न शक्तियां सौंपने की अनुमति देता है। विधायिका केवल मुख्य कानून और उसकी चाल की घोषणा करती है और उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह जनता के लिए उत्पन्न होने वाली प्रत्येक परिस्थिति को समझ सके और कल्पना कर सके कि हर स्थिति के लिए कानून की घोषणा कर सके। इस प्रकार, प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य कानून को पूरक करने की शक्तियाँ दी जाती हैं, न कि कानून के मुख्य प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने के लिए। अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत बोर्ड को अधिनियम की धारा 239 में निर्दिष्ट सीमा अवधि की समाप्ति के बाद रिफंड के लिए एक आवेदन को स्वीकार करने का निर्देश देने की शक्ति कानून के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन या ओवरराइड नहीं करती है। . यह भारत के संविधान

(1) 2004 266 आई.टी.आर. 489

के अनुच्छेद 265 और 300ए के अनुरूप है जो कर संग्रहण के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है। "कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा" और "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"। ये अनुच्छेद अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत पर आधारित हैं जो यह प्रावधान करता है कि बिना किसी अधिकार या वैधता के एकत्र किया गया कोई भी कर नागरिक को वापस किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 237 इन सिद्धांतों का प्रतीक है और यह आदेश देती है कि यदि किसी व्यक्ति ने उससे उचित रूप से वसूल की जाने वाली राशि से अधिक कर का भुगतान किया है, तो वह अतिरिक्त राशि की वापसी का हकदार होगा। हालाँकि, रिफंड का दावा करने की मशीनरी अधिनियम की धारा 239 में प्रदान की गई है जो सीमा की अवधि भी निर्धारित करती है जिस पर रिफंड के लिए दावा किया जा सकता है। हालाँकि, निर्धारित समय सीमा अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के संदर्भ में बोर्ड द्वारा छूट के अधीन है, जो कि सीमा अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के बराबर है और बोर्ड को कुछ परिस्थितियों में रिफंड के विलंबित दावा को दाखिल करने का अधिकार देता है।

(5) राजस्व के विद्वान वकील श्री राजेश बिंदल ने निम्नानुसार तर्क दिया: -

अधिनियम की धारा 119(2)(बी) विशेष रूप से प्रदान करती है कि बोर्ड, यदि वह वांछनीय या समीचीन समझता है, तो किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, प्राधिकारी को धन वापसी के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिकृत कर सकता है। निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद, कानून की कठोरता को कम करने और प्रावधान का निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 119 के तहत बोर्ड को शक्तियां सौंपी गई हैं। यह शक्ति निर्धारिती के लाभ के लिए प्रयोग योग्य है। उन्होंने भारत संघ और एक अन्य बनाम आजादी बचाओ आंदोलन और एक अन्य<sup>(2)</sup>, और यूको बैंक बनाम आयकर आयुक्त मामले में शीर्ष न्यायालय की मंशा पर भरोसा जताया<sup>3</sup>

उन्होंने एसोसिएटेडइलेक्ट्रो सेरामिक्स बनाम चैमन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(4)</sup> मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया, जिसमें राजस्व का तर्क था कि यदि किसी आयकर अधिकारी या किसी को कोई शक्ति नहीं दी गई थी दावा करने में देरी को माफ करने के लिए अन्य अधिकारी, बोर्ड भी समय नहीं बढ़ा सकता, अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर खारिज कर दिया गया। उन्होंने निम्नलिखित केस कानूनों पर भी भरोसा जताया, जिसमें अधिनियम की धारा 119(2)(बी) के तहत रिफंड का दावा करने में देरी की माफी के लिए निर्धारिती के दावे पर विचार किया गया था और इस आधार पर खारिज नहीं किया गया था कि कोई शक्ति मौजूद नहीं थी। विलंब क्षमा हेतु बोर्ड :-

- (i) गुजरात इलेक्ट्रो कंपनी बनाम आयकर आयुक्त<sup>(5)</sup>,
- (ii) धर्मपाल सिंह पाल बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(6)</sup>,
- (iii) कुसुमबेन एम. पारिख बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(7)</sup>,
- (iv) मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(8)</sup>, और
- (v) संत लाल बनाम भारत संघ और अन्य<sup>(9)</sup>, ।

(6) अधिनियम की धारा 237 इस प्रकार है:--

"237. यदि कोई व्यक्ति मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट करता है कि किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई कर की राशि या उसके द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई राशि उस राशि से अधिक है जिसके लिए वह इस अधिनियम के तहत उचित रूप से प्रभार्य है वर्ष, वह अतिरिक्त राशि की वापसी का हकदार होगा।"

- 
- (4) (1993) 201 आई.टी.आर. 501
  - (5) (2002) 172 सी.टी.आर. 220 (गुजरात)
  - (6) (2001) 250 आई.टी.आर. 629
  - (7) (2000) 242 आई.टी.आर. 501 (गुजरात)
  - (8) (1998) 233 1.टी.आर. 663
  - (9) (1996) 222 आई.टी.आर. 375

(7) अधिनियम की धारा 239 इस प्रकार है:-

"239. (1) इस अध्याय के तहत रिफंड के लिए प्रत्येक दावा निर्धारित तरीके से किया जाएगा और निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा।

(2) ऐसे किसी भी दावे की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह यहां निर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया गया हो, अर्थात्:-

(ए) जहां दावा उस आय के संबंध में है जो 1 अप्रैल 1967 को या उससे पहले शुरू होने वाले किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन योग्य है, ऐसे मूल्यांकन वर्ष के अंतिम दिन से चार साल;

(बी) जहां दावा उस आय के संबंध में है जो 1 अप्रैल, 1968 को शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन योग्य है; मूल्यांकन वर्ष के अंतिम दिन से तीन साल

(सी) जहां दावा उस आय के संबंध में है जो किसी अन्य मूल्यांकन वर्ष के लिए मूल्यांकन योग्य है, ऐसे मूल्यांकन वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष।"

(8) अधिनियम की धारा 237 से पता चलता है कि रिफंड के लिए दावा निर्धारण अधिकारी के समक्ष किया जाना है और रिफंड का दावा करने वाले व्यक्ति को मूल्यांकन अधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि उसके द्वारा भुगतान की गई कर की राशि उस राशि से अधिक है जो कि उचित रूप से प्रभार्य है। अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (1) उस तरीके को बताती है जिसमें रिफंड के लिए आवेदन किया जाना है। उपधारा (2) उस समय सीमा का निर्धारण करती है जिसके भीतर रिफंड का दावा किया जा सकता है। धारा 239 में, निर्धारण अधिकारी को उसके तहत निर्धारित अवधि के बाद धन वापसी के दावे पर विचार करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(9) हालाँकि, हमारे सामने सवाल यह है कि क्या बोर्ड के पास रिफंड के विलंबित दावे को स्वीकार करने की शक्ति है या नहीं। इस प्रयोजन के लिए, अधिनियम की धारा 119 का संदर्भ लेना होगा, जो इस प्रकार है:-

"119. (1) बोर्ड, समय-समय पर, अन्य आयकर अधिकारियों को ऐसा आदेश, निर्देश जारी कर सकता है जो इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए उपयुक्त समझे जाएं, और ऐसे अधिकारी और इस अधिनियम के निष्पादन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति ऐसे आदेशों, निर्देशों और निर्देशों का पालन करेंगे।

तख़्ता:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश, निर्देश या दिशा-निर्देश जारी नहीं किया जाएगा:-

(ए) ताकि किसी भी आयकर प्राधिकरण को एक विशेष मूल्यांकन करने या किसी विशेष मामले को एक विशेष तरीके से निपटाने की आवश्यकता हो; या

(बी) ताकि इस अपीलीय कार्यों के अभ्यास में आयुक्त (अपील) के निर्देश में हस्तक्षेप किया जा सके।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,-

(ए) बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो राजस्व के मूल्यांकन और संग्रहण के कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से, समय-समय पर जारी कर सकता है (चाहे किसी छूट के माध्यम से) प्रावधानों का धारा 139, 143, 144, 147, 148, 154, 155, 158 बीएफए, धारा 201 की उपधारा (1ए), धारा 210, 211, 234ए, 234बी, 234सी, 271 और 273 या अन्यथा), सामान्य या विशेष आय के किसी भी वर्ग या मामलों के वर्ग के संबंध में आदेश, दिशा-निर्देश या निर्देश निर्धारित करना (राजस्व के मूल्यांकन या संग्रह से संबंधित कार्य में अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निर्धारित के लिए प्रतिकूल नहीं होना) या जुर्माना लगाने के लिए कार्यवाही शुरू करना और ऐसा कोई भी आदेश, यदि बोर्ड की राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो सामान्य जानकारी के लिए निर्धारित तरीके से प्रकाशित और प्रसारित किया जा सकता है;

(बी) बोर्ड, यदि वह किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी आयकर प्राधिकारी को, जो आयुक्त (अपील) नहीं है, अधिकृत

कर सकता है। इस अधिनियम के तहत किसी भी छूट, कटौती, धनवापसी या किसी अन्य राहत के लिए आवेदन या दावा करने के लिए इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद एक आवेदन या दावा स्वीकार करें और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उससे निपटें;

(सी) बोर्ड, यदि वह किसी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए ऐसा करना वांछनीय या समीचीन समझता है, तो उसमें निर्दिष्ट कारणों के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, किसी भी प्रावधान में निहित किसी भी आवश्यकता को शिथिल कर सकता है। अध्याय IV या अध्याय V-ए का, जहां निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अधीन कटौती का दावा करने के लिए ऐसे प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है, अर्थात्: -

(i) ऐसी आवश्यकता के अनुपालन में चूक निर्धारित के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई थी; और

(ii) निर्धारित ने पिछले वर्ष के संबंध में मूल्यांकन पूरा होने से पहले ऐसी आवश्यकता का अनुपालन किया है जिसमें ऐसी कटौती का दावा किया गया है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार इस खंड के तहत जारी किए

(10) **आजादी बचाओ आंदोलन (सुप्रा)** में, शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की उपधारा 119(2) के खंड (ए) के दायरे पर विचार किया है जो गए प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। "बोर्ड को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की कठोरता को जारी करके शिथिल करने का अधिकार देता है। सामान्य या विशेष आदेश यदि वह मूल्यांकन कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है। पृष्ठ 727 पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है:-

"धारा 119, रणनीतिक रूप से अध्याय XIII में रखी गई है जो "आयकर अधिकारियों" से संबंधित है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की एक सक्षम शक्ति है, जिसे धारा 116 (ए) के तहत आयकर अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस धारा के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अन्य



आयकर अधिकारियों को ऐसे आदेश, निर्देश और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार है "जैसा कि यह इस अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए उपयुक्त हो सकता है"। ऐसे प्राधिकरण और इसके कार्यान्वयन में नियोजित अन्य सभी व्यक्ति अधिनियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ऐसे आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। धारा 119 की उप-धारा (1) का प्रावधान इस शक्ति के दो अपवादों को मान्यता देता है। पहला, कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड प्रत्यक्ष करों को किसी भी आयकर प्राधिकारी को विशिष्ट मूल्यांकन करने या किसी विशेष मामले को किसी विशेष तरीके से निपटाने की अपेक्षा नहीं करता। दूसरा, इस अपीलीय कार्यों के अभ्यास में आयुक्त (अपील) के विवेक के साथ हस्तक्षेप के संबंध में है। धारा 119 की उपधारा (2) कुछ विशेष मामलों में शक्ति के प्रयोग का प्रावधान करती है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सक्षम बनाती है, यदि वह कार्य के उचित और कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है। राजस्व के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए, आय के किसी भी वर्ग या मामलों के वर्ग के संबंध में सामान्य या विशेष आदेश जारी करने के लिए, अन्य आयकर अधिकारियों द्वारा निर्वहन में दिशानिर्देशों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में दिशा-निर्देश या निर्देश निर्धारित करना। जुर्माना लगाने के लिए मूल्यांकन या कार्यवाही शुरू करने से संबंधित उनके काम का। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि वह खंड (ए) में उल्लिखित कई वर्गों के प्रावधानों से छूट देने में सक्षम है। ऐसे आदेशों को निर्धारित तरीके से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जा सकता है, यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की राय है कि यह बहुत आवश्यक है। शक्ति के प्रयोग पर एकमात्र बाधा यह है कि यह निर्धारित के लिए प्रतिकूल नहीं है। हम वर्तमान अपीलों में खंड (बी) और (सी) के प्रावधानों से चिंतित नहीं हैं।"

(10.1) न्यायालय ने **के.पी.वर्गीस बनाम आयकर अधिकारी, एर्नाकुलम और अन्य<sup>(10)</sup>**, और **एलरमैन लाइन्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल आई.<sup>(11)</sup>**, में अपने पहले के फैसलों का भी उल्लेख किया ताकि यह देखा जा सके कि परिपत्र और धारा 119 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा जारी निर्देश कर विभाग का प्रशासन करने वाले अधिकारियों पर बाध्यकारी थे, भले ही वे उप-धारा (2) की सही व्याख्या के अनुसार

(10) (1981) 131 आई.टी.आर. 597

(11) (1971) 82 आई.टी.आर. 913

नहीं पाए जाते और वे ऐसे निर्माण से रोकते या विचलित होते। **कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बनाम धीरेन केमिकल इंडस्ट्रीज**<sup>(12)</sup> मामले में इसके फैसले का भी संदर्भ दिया गया था। उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त वाक्यांश की व्याख्या से निपट रहा था। हालाँकि, व्याख्या देने के बाद, यह देखा गया कि यदि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने उक्त वाक्यांश पर एक अलग व्याख्या रखते हुए परिपत्र जारी किया था, तो वह व्याख्या राजस्व पर बाध्यकारी होगी। दूसरे शब्दों में, बोर्ड द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के तहत जारी किए गए परिपत्रों को आयकर अधिकारियों के लिए बाध्यकारी माना जाता था यदि यह किसी विशेष वाक्यांश या प्रावधान की व्याख्या पर आधारित था जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के साथ विरोधाभासी था। उच्चतम न्यायालय ने यूको बैंक (सुप्रा) में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों (पेज 896 पर) पर भी भरोसा जताया -

"इस तरह के निर्देश वहां निर्दिष्ट अनुभागों के किसी भी प्रावधान में छूट के माध्यम से या अन्यथा हो सकते हैं। बोर्ड के पास, अन्य बातों के अलावा, कानून की कठोरता को कम करने और इसके प्रावधानों का निष्पक्ष कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की शक्ति है, जारी करके आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिपत्र जो अधिनियम के प्रशासन में अधिकारियों पर बाध्यकारी हैं। हालाँकि, धारा 119(2)(ए) के तहत, उसमें दिए गए परिपत्र प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। निर्धारित। इस प्रकार, जो प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपने लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करता है, उसे कानून की कठोरता में ढील देकर या निर्धारित अन्य अनुमेय तरीकों से लाभ को त्यागने का अधिकार दिया जाता है, जब इसे उस तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होती है जिसे वह मानता है। धारा 119 में नीचे। यह शक्ति मूल्यांकन के कार्य के उचित, और कुशल प्रबंधन और सार्वजनिक हित के उद्देश्य से दी गई है। यह राजकोषीय कानून के उचित प्रशासन के लिए बोर्ड को दी गई एक लाभकारी शक्ति है ताकि अनुचित कठिनाई न हो। निर्धारित के कारण हो और राजकोषीय कानूनों को सही ढंग से लागू किया जा सके। कठिन मामले जिन्हें उचित रूप से एक वर्ग से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, उन्हें कर अधिकारियों पर बाध्यकारी परिपत्र जारी करके कानून में छूट का लाभ दिया जा सकता है।" (जोर दिया गया)

(10.2) सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः माना कि अधिनियम की धारा 119 के तहत बोर्ड की

(12) (2002) 254 आई.टी.आर. 554

शक्ति पर एकमात्र प्रतिबंध "किसी विशेष निर्धारिती के मूल्यांकन के दौरान या आय आयुक्त के विवेक के दौरान हस्तक्षेप करने से रोकना है।" कर (अपील)"।

(11) यह सच है कि उपर्युक्त टिप्पणियाँ अधिनियम की धारा 119(2) के खंड (ए) के संदर्भ में की गई हैं, लेकिन हमारा विचार है कि यह खंड पर भी पूरी ताकत से लागू होगा ( बी) उक्त प्रावधान के. खंड (ए) उसमें उल्लिखित कई वर्गों के प्रावधानों से छूट देने की शक्ति से संबंधित है। खंड (बी) किसी भी मामले या वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए परिसीमा की अवधि से छूट देने की शक्ति से संबंधित है मामले. **एसोसिएटेड इलेक्ट्रो सेरामिक्स (सुप्रा)** में, यह माना गया कि भले ही रिफंड के लिए दावा करने में देरी को माफ करने के लिए किसी आयकर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को कोई शक्ति नहीं दी गई थी, लेकिन ऐसी शक्ति विशेष रूप से धारा के तहत बोर्ड को प्रदान की गई थी। अधिनियम की धारा 119(2)(बी). राजस्व का यह तर्क कि बोर्ड के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, को एस.राजेंद्र बाबू, जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया था: -

"विभाग के विद्वान वकील का यह तर्क कि यदि आयकर अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के रूप में इस तरह का दावा करने में देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, तो बोर्ड भी समय नहीं बढ़ा सकता, सही नहीं होगा, क्योंकि यह प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि, जहां कोई समय सीमा तय की गई है, ऐसे समय को बोर्ड द्वारा बढ़ाया जा सकता है या देरी को माफ किया जा सकता है।"

(12) किसी भी मामले या मामलों की श्रेणी में होने वाली वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए निर्दिष्ट अवधि के बाद दायर किसी आवेदन या दावे या रिटर्न को स्वीकार करने की धारा 119(2)(बी) के तहत बोर्ड की शक्ति को जॉन शैलेक्स पेंट्स में भी मान्यता दी गई है। (पी) लिमिटेड बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(13)</sup>, एचएस अनाथरमैया बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य<sup>(14)</sup>, पल्लवन ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य<sup>(15)</sup>, मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड। (सुप्रा), कुसुमबेन एम. पारिख का मामला (सुप्रा), और धर्मपाल सिंह पाल का मामला (सुप्रा)। रिफंड के लिए

(13) (1993) 201 आई.टी.आर. 523 (कर.)

(14) (1993) 201 आई.टी.आर. 526 (कर.)

(15) (1998) 233 आई.टी.आर. 745 (मद.)

(एन.के. सूद, जे.) (एफ.बी.)

हस्तक्षेप करता है और न ही आयकर आयुक्त (अपील) के विवेक में हस्तक्षेप करता है, जो आजादी बचाओ आंदोलन (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। अधिनियम की धारा 119 के तहत बोर्ड की शक्तियों पर एकमात्र प्रतिबंध।

(13) मामले को दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5, किसी आवेदन को परिसीमा अवधि से परे स्वीकार करने की अनुमति देती है यदि आवेदन न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है। ऐसी अवधि के भीतर. इस प्रावधान का सामान्य अनुप्रयोग है. हालाँकि, इस सामान्य नियम से हटकर उक्त अधिनियम की धारा 29(2) में कहा गया है, जो इस प्रकार है:-

"(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा अवधि निर्धारित करता है, धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा किसी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जिस हद तक, और जिस हद तक, वे हैं। ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।

(13.1) उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सीमा अधिनियम की धारा 5 विशेष या स्थानीय कानूनों के मामलों में उस हद तक लागू होगी, जिस हद तक उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानूनों द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है। दूसरे शब्दों में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का सहारा केवल तभी नहीं लिया जा सकता जब इसे किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया हो।

(13.2) अधिनियम की धारा 239 ने सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 239 और 119(2) को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रिफंड के दावों के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन को विशेष रूप से अधिनियम में शामिल किया गया है।

(13.3) इस प्रकार. हमारे विचार में अधिनियम की धारा 119(2) के तहत बोर्ड को विलंबित दावे पर विचार करने के लिए दी गई शक्ति सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों को शामिल करने के अलावा और कुछ नहीं है।

(14) उपरोक्त के मद्देनजर, हम संतुष्ट हैं कि अधिनियम की धारा 119(2) के तहत बोर्ड को प्रदत्त शक्ति के आधार पर, किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए अधिनियम की धारा 239 के तहत निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी धन वापसी के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ।

(14.1) इसलिए, हम निरंजन दास (सुप्रा) में डिवीजन बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर सहमति देने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता का अवधि में छूट का दावा अधिनियम की धारा 119 के तहत परिसीमा को निम्नलिखित शर्तों में खारिज कर दिया गया है:-

"हमने रिट याचिका में उद्धृत अधिनियम की धारा 119 का अवलोकन किया है। हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि अधिनियम की धारा 239 के तहत शामिल वैधानिक प्रावधान, अधिनियम की धारा 119 तहत निर्देशों के माध्यम से बोर्ड के हाथों छूट के लिए उत्तरदायी है।

(14.2) उपरोक्त निष्कर्ष विशेष रूप से अधिनियम की धारा 119(2) के प्रावधानों से संबंधित नहीं है और न ही ऊपर चर्चा की गई विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को ध्यान में रखता है।

(14.3) तदनुसार, हम **निरंजन दास (सुप्रा)** में निर्धारित अनुपात को खारिज कर देते हैं।

(15) हम संदर्भ का उत्तर सकारात्मक देते हैं।

(16) अब मामले को डिवीजन 13/13 एच के समक्ष रखा जाएगा

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी